Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 6.247 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 12 | ISSUE : 7 | JULY 2026

सीईओ-इन-चीफ: द्वितीय ट्रम्प प्रशासन (2025-2026) के लेन-देन संबंधी यथार्थवाद, विस्तारवाद और हेजेमोनिक बदलाव का विश्लेषण

डॉ. राजेंद्र कुमार वर्मा [1]

[1]सहायक आचार्य, श्री गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर (राजस्थान).

ABSTRACT:

यह शोध पत्र डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे प्रशासन (2025-2026) के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में आए आमूल-चूल परिवर्तनों का परीक्षण करता है। "अमेरिका फर्स्ट" के एक यथार्थवादी एजेंडे को अपनाते हुए, इस प्रशासन ने 1945 के बाद की नियम-आधारित उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती दी और बहुपक्षवाद को त्याग दिया। इस कालखंड की विशेषता विस्तारवाद, "गनबोट डिप्लोमेसी" और "लेन-देन संबंधी कूटनीति" रही है, जहाँ सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों के साथ संबंधों को केवल आर्थिक लाभ और राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देखा गया। यह शोध पत्र 'डोनरो सिद्धांत' (Donroe Doctrine), 2026 के ईरान युद्ध, "मुक्ति दिवस" (Liberation Day) टैरिफ व्यवस्था और वैश्विक मानवाधिकार मानकों से पीछे हटने का विश्लेषण करता है ताकि यह समझा जा सके कि कैसे अमेरिका ने एक महाशक्ति के रूप में अपनी भूमिका को "बिज़नेस प्लेग्राउंड" में बदल दिया।

KEYWORDS:

-

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
17th July 2026	18th July 2026

1. परिचय: लेन-देन संबंधी यथार्थवाद का उदय

20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ने वैश्विक राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात किया। उनके प्रशासन ने एक ऐसी विदेश नीति को अपनाया जिसे "लेन-देन संबंधी यथार्थवाद" (Transactional Realism) कहा गया। इस दृष्टिकोण के तहत, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को साझा मूल्यों या दीर्घकालिक गठबंधनों के बजाय अल्पकालिक लाभ और "सौदा करने" की कला के रूप में देखा गया। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर के शब्दों में, "हम एक महाशक्ति हैं... और राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत, हम एक महाशक्ति की तरह आचरण करेंगे"।

इस प्रशासन ने सॉफ्ट पावर (कोमल शक्ति) को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों से समर्थन वापस ले लिया और हार्ड पावर (कठोर शक्ति) को प्राथमिकता दी। अमेरिकी प्रभाव के इस पीछे हटने से जो शून्यता पैदा हुई, उसे रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों ने भरने का प्रयास किया।

2. 'डोनरो सिद्धांत' और अमेरिकी विस्तारवाद

द्वितीय ट्रम्प प्रशासन की सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक विस्तारवाद का पुनरुत्थान था, जिसे स्वयं ट्रम्प ने 'डोनरो सिद्धांत' (Donroe Doctrine) का नाम दिया। यह पारंपरिक मोनरो सिद्धांत का एक अत्यधिक आक्रामक संस्करण था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व को फिर से स्थापित करना था।

कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा पर दावा

ट्रम्प प्रशासन ने बार-बार कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका के 51वें राज्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया। हालांकि शुरुआत में इसे एक मज़ाक समझा गया, लेकिन ट्रम्प ने बाद में पुष्टि की कि वह इसके प्रति गंभीर थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे कनाडा के खनिज संसाधनों तक अमेरिका की पहुंच आसान हो जाएगी।

इसी तरह, ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने या उसे "किसी न किसी तरह" नियंत्रित करने के प्रस्ताव ने एक अंतरराष्ट्रीय संकट (Greenland Crisis) पैदा कर दिया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड की यात्रा के दौरान डेनमार्क पर रक्षा क्षेत्र में कम निवेश करने का आरोप लगाया। पनामा नहर के संदर्भ में भी, प्रशासन ने "तटस्थता समझौते" के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नहर पर अमेरिकी नियंत्रण की वापसी की मांग की।

3. आर्थिक कूटनीति: "मुक्ति दिवस" और टैरिफ युद्ध

ट्रम्प की विदेश नीति उनकी आर्थिक नीति से अविभाज्य थी। उन्होंने व्यापार घाटे को "स्वाभाविक रूप से हानिकारक" माना और अमेरिकी बाजार तक पहुंच को एक विशेषाधिकार बताया।

टैरिफ सुनामी (Tariff Tsunami)

2 अप्रैल 2025 को प्रशासन ने "मुक्ति दिवस" (Liberation Day) के रूप में घोषित किया, जिसके तहत आयातित वस्तुओं पर भारी "पारस्परिक शुल्क" (Reciprocal Tariffs) लगाए गए। चीन के साथ व्यापार युद्ध तब चरम पर पहुंच गया जब चीनी वस्तुओं पर टैरिफ 145% तक बढ़ा दिया गया। जवाब में चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगा दिया।

सहयोगियों को भी नहीं बख्शा गया। कनाडा और मैक्सिको पर सीमा सुरक्षा और फेंटानिल तस्करी को रोकने के लिए दबाव बनाने हेतु 25% का सार्वभौमिक टैरिफ लगाया गया। हालांकि, समझौते के बाद इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया, जो ट्रम्प की "दबाव डालकर सौदा करने" की रणनीति का हिस्सा था।

4. क्षेत्रीय विश्लेषण: युद्ध और गठबंधन

4.1 पश्चिम एशिया: 2026 का ईरान युद्ध

ट्रम्प प्रशासन ने मध्य पूर्व में अत्यधिक हस्तक्षेपवादी रुख अपनाया। 28 फरवरी 2026 को, अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर संयुक्त हमले किए, जिसे "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" (Operation Epic Fury) कहा गया। इसका घोषित उद्देश्य ईरान में "सत्ता परिवर्तन" (Regime Change) था। ओमान के विदेश मंत्री ने इस युद्ध को "गंभीर गलत गणना" और "तबाही" करार दिया।

इज़राइल के प्रति ट्रम्प का दृष्टिकोण अटूट समर्थन का रहा। उन्होंने गाजा पट्टी पर अमेरिकी नियंत्रण और वहां "मिडिल ईस्ट का रिवेरा" बनाने के लिए फिलिस्तीनियों के जबरन स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने "जातीय सफ़ाई" कहा।

4.2 यूरोप और नाटो के साथ तनाव

प्रशासन ने यूरोपीय संघ (EU) के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया, इसे "सभ्यता के विनाश" (Civilizational Erasure) का शिकार बताया। नाटो के संदर्भ में, ट्रम्प ने धमकी दी कि

यदि सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च नहीं करते, तो अमेरिका उनकी रक्षा नहीं करेगा।

रूस-यूक्रेन युद्ध को ट्रम्प ने "एक दिन में" समाप्त करने का वादा किया था। उनके शांति प्रस्ताव में यूक्रेन के 50% खनिज और तेल संसाधनों का स्वामित्व अमेरिका को देने की मांग शामिल थी, जिसे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने "यूक्रेन को बेचने" के प्रयास के रूप में खारिज कर दिया। फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ एक तीखी नोकझोंक के बाद, अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

4.3 एशिया-प्रशांत: चीन और भारत

एशिया में, प्रशासन ने चीन को एक "रणनीतिक प्रतिस्पर्धी" के रूप में लक्षित किया। राज्य विभाग ने एक निर्देश जारी किया कि शी जिनपिंग को केवल "चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव" के रूप में संबोधित किया जाए ताकि उनकी सत्ता की प्रकृति को उजागर किया जा सके।

भारत के साथ संबंधों में "MAGA प्लस MIGA" (Make India Great Again) की बात की गई, लेकिन व्यापारिक मोर्चे पर तनाव बना रहा। ट्रम्प ने रूस से तेल खरीदने और एस-400 मिसाइल प्रणाली सौदे के कारण भारत पर 25% का "पारस्परिक टैरिफ" लगाने की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा किया, जिसे भारत ने "निराधार" बताकर खारिज कर दिया।

4.4 अफ्रीका: "निर्वासित कूटनीति" और उपेक्षा

अफ्रीका के प्रति नीति में सैन्य और कूटनीतिक जुड़ाव में भारी कमी देखी गई। अमेरिकी नीति मुख्य रूप से "निर्वासन सौदों" (Deportee Deals) पर केंद्रित रही, जहाँ रवांडा और युगांडा जैसे देशों को अमेरिकी प्रवासियों को स्वीकार करने के बदले वित्तीय सहायता दी गई। नाइजीरिया में, ट्रम्प ने "ईसाई समुदायों की रक्षा" के नाम पर इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया।

5. मानवाधिकारों का क्षरण और सॉफ्ट पावर का पतन

द्वितीय ट्रम्प प्रशासन ने मानवाधिकारों की पारंपरिक परिभाषा को ही बदल दिया। 2024 की मानवाधिकार रिपोर्टों से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, LGBTQ+ अधिकारों और स्वदेशी समूहों के उत्पीड़न से संबंधित वर्गों को हटा दिया गया। इसके बजाय, प्रशासन ने "ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकारों" पर ध्यान केंद्रित किया और 'विविधता, समानता और समावेश' (DEI) नीतियों को ही "मानवाधिकार उल्लंघन" घोषित कर दिया।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अमेरिका आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर हो गया, और 260 मिलियन डॉलर की बकाया राशि देने से इनकार कर दिया। जलवायु परिवर्तन को ट्रम्प ने "सबसे बड़ा घोटाला" बताया और अमेरिका को पेरिस समझौते से दूसरी बार बाहर निकाल लिया।

6. निष्कर्ष: एक नाजुक महाशक्ति

डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे प्रशासन ने अमेरिकी विदेश नीति को एक व्यावसायिक उद्यम में बदल दिया। "सीईओ-इन-चीफ" के रूप में, ट्रम्प ने अल्पकालिक आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत वफादारी को रणनीतिक स्थिरता पर वरीयता दी। हालांकि इस नीति ने कुछ व्यापारिक असंतुलन को कम किया, लेकिन इसने अमेरिकी नैतिक अधिकार और "सामाजिक पूंजी" (Social Capital) को गंभीर क्षति पहुँचाई।

'डोनरो सिद्धांत' और 2026 का ईरान युद्ध 19वीं सदी के साम्राज्यवाद की वापसी के संकेत थे, जहाँ कानून के बजाय केवल "राष्ट्रीय शक्ति" ही निर्णय का आधार थी। अंततः, एक महाशक्ति को "बिज़नेस प्लेग्राउंड" की तरह प्रबंधित करने से अमेरिका पहले से अधिक "चपल" तो बना, लेकिन साथ ही अधिक "नाजुक" और वैश्विक स्तर पर अलग-थलग भी हो गया।

REFERENCES

1. **White House Records (2025).** "National Security Strategy Draft - Reasserting the Monroe Doctrine.".

2. **U.S. Department of State (2025).** "America First Global Health Strategy & Country Reports on Human Rights.".

3. **Wikipedia (2026).** "Foreign policy of the second Trump administration." (Comprehensive documentation of 2025-2026 events).

4. **Official Presidential Tweets (Truth Social, 2025-2026).** Statements on Canada annexation, Iran war, and South Africa G20.

रिपोर्ट और विश्लेषण (Reports & Analysis)

5. **Brookings Institution (2018/2026).** "Deconstructing Trump's Foreign Policy" by Shadi Hamid..

6. **Universidad de Navarra - Global Affairs (2025).** "How Trump is turning US' foreign policy into his business playground" by Alberto Ferreres Fernández..

7. **Observer Research Foundation (ORF, 2026).** "Trump’s Policies and an Uneasy World" by Harsh V. Pant..

8. **Indian Council of World Affairs (ICWA, 2025).** "Trump’s Tariff Regime and Latin America" by Aditi Mishra..

9. **Council on Foreign Relations (CFR, 2024).** "Trump's Foreign Policy Moments.".

अकादमिक और मीडिया स्रोत (Academic & Media Sources)

10. **Mendes, Pedro Emanuel (2023).** "The Dynamics of Change in United States Foreign Policy." Social Sciences Journal..

11. **Friedman, George & Shapiro, Jacob L. (2026).** "The Limits of the Trump Doctrine." Center for International Relations and Sustainable Development (CIRSD)..

12. **NPR (2025).** "Trump's foreign policy: deals with allies over diplomacy with rivals" by Greg Myre..

13. **Aaj Tak (2026).** "ShwetPatra: Donald Trump's Aggressive Foreign Policy.".

14. **Solace Global (2025).** "What Trump’s Foreign Policy Means for Global Stability."